श्री सीताराम येचुरी: सर, आप कह रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: हां, मैंने कह दिया है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, आप लिखित जवाब पढ़िए, जितना पैसा ये वकीलों को लिटिगेशन में दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: छोड़िए... छोड़िए, आगे भी ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: केसेज लड़ने के लिए ये जितना दे रहे हैं, उतने में तो ये स्वतंत्रता सम्मान पेंशन दे देते। उसमें तो दस स्वतंत्रता सम्मान पेंशन मिल जाएं।

Increase of pay scales of Army personnel

*485. MS. SUSHILA TIRIYA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal to increase the pay scales of Army personnel;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the increase in pay will cover all the three services of Armed Forces?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M.PALLAM RAJU): (a) to (c) Government has set up the Sixth Central Pay Commission to go into the question of pay, allowances and other facilities/benefits of Central Government Employees including Armed Forces Personnel. The three services have submitted a joint memorandum to the Sixth Central Pay Commission seeking increase in Pay Scales, enhancement of existing allowances, introduction of new allowances etc.

सुश्री सुशीला तिरिया: सर, मेरा पहला सप्लीमेंटरी यह है कि आजकल डिफेंस में जिस तरह से आर्मीज़ को तनख्वाह दी जा रही है, एक कॉल सेंटर से भी कम तनख्वाह दी जा रही है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी, रिप्लाई तो उन्होंने दिया है कि अभी भी कंसिडरेशन में है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी में सांसदों द्वारा डिमांड करने के बावजूद भी उनका पे-स्केल अभी तक बढ़ाया नहीं गया है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या यंगस्टर्स को

बढ़ावा देने के लिए, डिफेंस में भरती करने के लिए क्या कदम मंत्री जी अपने डिपार्टमेंट से उठा रहे हैं और मैं यह भी जानना चाहूंगी कि 2001 से 2004 से बहुत सारे ऑफिसर्स ने एप्लाई किया हुआ है आर्मी छोड़ने के लिए, तो इसमें कितना सच है? कितनों ने एप्लाई किया और कितने छोड़ चुके हैं?

श्री सभापति: बोलिए, बोलिए, जवाब दीजिए।

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Sir, the Government is empathetic about the fact that the pay scales are not commensurate with what should be given to the Forces, but the matter has been referred to the Central Pay Commission. It is under examination by the Central Pay Commission. The Central Pay Commission would come out with its recommendations by April 2008.

सुश्री सुशीला तिरिया : सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि क्या सेंट्रल पे कमीशन में किसी रिटायर्ड ऑफिसर को मैम्बर रखा है? अगर मैम्बर रखा है, तो यह जानना चाहूंगी कि रिटायर्ड ऑफिसर को मिलने वाला जो भत्ता है, जो पैसे हैं, लीगल नोटिस देने के बाद, डिफेंस सेक्रेटरी के पास अभी तक कितने पेंडिंग हैं और कितने दे चुके हैं?

श्री सभापति: मंत्री जी, कुछ जवाब देंगे, फिर क्वेश्चन ऑवर ओवर होने वाला है।

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Sir, the Standing Committee had also recommended that there should be inclusion of an Armed Forces officer in the Central Pay Commission. That request has not been acceded to, but the matter is under examination by the Central Pay Commission.

As regards the number of payments that are outstanding, I don't think that falls within the purview of this question and I would request the hon. Member of Parliament to pose a separate question on that.

सुश्री सुशीला तिरिया : सर, इसके ऊपर डिसकशन होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, ये जो इतना लड़ते-झगड़ते हैं और देश के खिलाफ ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: डिसकशन होना चाहिए , ...(व्यवधान)... आप रूल्स, ...(व्यवधान)... आप रूल्स, ...(व्यवधान)... बैठिए , बैठिए , Question hour is over.